

दैनिक भारत कि

तामीर

संपादक - काज़ी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

बीड (महाराष्ट्र)	वर्ष-१ ला	अंक-१७५ वा	शनिवार २५ जनवरी २०२५	RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024	किमत : २ रुपये	पन्ने - ४
------------------	-----------	------------	----------------------	---	----------------	-----------

वक्फ विधेयक को लेकर, संयुक्त सदस्य समिति में हंगामा, असद अवेसी समेत दस सांसद निलंबित

नई दिल्ली। समाचार एजेंसी विवादित वक्फ विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की ५०० पन्नों की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। इस रिपोर्ट पर शुक्रवार और शनिवार को चर्चा के लिए दो दिवसीय बैठक बुलाई गई थी। लेकिन, आज बैठक के पहले ही दिन सांसदों के बीच हंगामा हो गया, जिसके चलते अब विपक्षी दलों के १० सांसदों को समिति से निलंबित कर दिया गया है। निलंबित सांसदों में शिवसेना (ठाकरे) के अरविंद सावंत और असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। इस बैठक में रिपोर्ट पर चर्चा के बाद इसे विधि मंत्रालय को सौंपा जाना था। इस बार के बजट सत्र में यह विधेयक पेश किए जाने की संभावना है।

भाजपा सांसद जगदीश पाल इस संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि आज हमने जम्मू-कश्मीर के शिष्टमंडल मीरवाइज उमर फारूक को उनका पक्ष रखने का समय दिया था। लेकिन, संसद में विधेयक की चर्चा में भाग न लेने वाले असदुद्दीन ओवैसी आज चर्चा में शामिल हुए। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने मुझसे अशिष्ट व्यवहार किया और असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। मैं उन्हें शांत रहने की अपील कर रहा था, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। आखिरकार, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया।

निलंबित किए गए सांसदों में कल्याण

बनर्जी, मोहम्मद जावेद, ए. राजा, असदुद्दीन ओवैसी, नसीर हुसैन, मोहिबुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला, अरविंद सावंत, नदीम-उल-हक और इमरान मसूद का नाम शामिल है। आज की बैठक की शुरुआत ही हंगामे से हुई। विपक्षी दलों के सांसदों ने आरोप लगाया कि विधेयक में जो बदलाव सुझाए गए हैं, उनका अध्ययन करने के लिए उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, जिन्हें संसदीय समिति से निलंबित कर दिया गया, ने कहा कि सरकार वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण चाहती है। लोकसभा में पेश किए गए वक्फ विधेयक में ४४ संशोधन सुझाए गए हैं। इन संशोधनों पर जेपीसी की दो दिवसीय बैठक



में विस्तार से चर्चा होगी थी। राज्यों के वक्फ बोर्डों के पास १९५० में ३५ हजार जमीनें थीं, लेकिन पिछले ७५ वर्षों में इनकी संख्या बढ़कर १० लाख हो गई है। जेपीसी में भाजपा के सहायक सदस्यों ने आरोप लगाया है कि वक्फ बोर्ड ने इनमें से कई जमीनों पर

कब्जा कर लिया है। इन जमीनों के स्वामित्व को लेकर पूर्व प्रभाव से समीक्षा करने की मांग समिति में की गई। जेपीसी की अब तक हुई ३४ बैठकों में से अधिकांश बैठकें विवादित रही हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बार

बैठक में बोलत तक तोड़ दी थी। कंग्रेस, डीएमके, शिवसेना (ठाकरे) समेत अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने विधेयक में किए गए संशोधनों का कड़ा विरोध किया है। आज की बैठक में भी यही स्थिति देखने को मिली।

उद्धव ठाकरे की हालत शोले के असरानी जैसी-मंत्री आशीष शेलार

विशेष संवाददाता मुंबई: उद्धव ठाकरे की हालत शोले फिल्म के असरानी जैसी होने वाली है, इसलिए वे कह रहे हैं कि वे अकेले लड़ेंगे। आधुनिक महाराष्ट्र के विश्वासघाती नेता के रूप में उद्धव ठाकरे की पहचान है, ऐसा तीखा आरोप सूचना प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार ने किया है।



उद्धव ठाकरे के कल के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए शेलार ने 'एक्स' पर पोस्ट के जरिए निशाना साधा। शेलार ने लिखा, श्रीमान उद्धव ठाकरे का जन्म २७ जुलाई १९६० को हुआ था। इसलिए, १९५१ में स्थापित जनसंघ के बारे में उन्हें जानकारी होना संभव नहीं है। ५ और ६ अप्रैल १९८० को दिल्ली में जनसंघ के नेताओं की बैठक हुई थी, जिसमें एक नए राजनीतिक दल की स्थापना का निर्णय लिया गया। उस समय उनकी उम्र केवल २० वर्ष थी। इसलिए, इस संबंध में भी उन्हें जानकारी नहीं हो सकती।

आप जनसंघ और भाजपा की स्थापना पर, १०० साल पूरे करने वाले संघ पर बोलते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया

भर में देश का सम्मान बढ़ाया और भाजपा को दुनिया का नंबर एक दल बनाया। जिन अमित भाई शाह ने यह कर दिखाया, उनके बारे में आप बात करते हैं? समाजवादियों की किताबें पढ़कर आपको महाराष्ट्र और जनसंघ का इतिहास समझ नहीं आएगा। आप अमित भाई शाह की पीठ पर चोट के निशान डालने की बात कर रहे हैं? किस बात के? कब? पहले आप अपने पिता, हिंदूध्दयसंप्राट बालासाहेब ठाकरे, जो २६ जुलाई की बाढ़ में फंसे थे, उस समय की घटना याद कीजिए। उस समय आप मिठी नदी की बाढ़ को छोड़कर पंचतारा होटल में भाग गए थे। उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के निशान आपकी पीठ और जीवन पर गहरे हैं। कभी मातोश्री के शीशे के सामने खड़े होकर इन्हें देखिए। ठेकेदारों से कमीशन खाकर आपने मुंबई का जो बुरा हाल किया है, उसके घाव दो करोड़ मुंबईकरों के दिलों पर हैं। उनकी झुर्रियां क्या आपको अपने चेहरे पर दिखती हैं? यह भी शीशे से पूछकर देखिए। तब आपको पता चलेगा कि घाव गहरे हैं या आपके दिमाग में ही कोई गड़बड़ है, इन तीखे शब्दों में उन्होंने पलटवार किया।

स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव की तैयारी में जुटे: अजित पवार

नांदेड़ में विभिन्न दलों के पदाधिकारियों ने राष्ट्रवादी में प्रवेश किया



मुंबई: स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव में अधिक से अधिक सदस्यों को विजयी बनाने के लिए प्रयास करें और चुनाव को ध्यान में रखते हुए तैयारी शुरू करें। यह आह्वान राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार ने किया। गुरुवार को नांदेड़ जिले के नायागांव विधानसभा क्षेत्र के लगभग ५० गांवों के विभिन्न दलों के पदाधिकारियों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश किया। इस अवसर पर उन्होंने मार्गदर्शन करते हुए कहा कि नांदेड़ जिले और शहर में पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए प्रयास करें। इसके लिए जरूरी हर सहयोग पार्टी और सरकार की ओर से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान शुरू किया गया है। सभी वर्गों के अधिक से अधिक लोग इसमें कैसे शामिल हों, इस पर ध्यान दें। स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन हुआ है। जनता ने

अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी समस्याओं का समाधान करें। पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखना चाहिए। इसी दिशा में पार्टी कार्यो का ढांचा तैयार किया जा रहा है और आवश्यक कार्यक्रम दिए जाएंगे। पवार ने यह भी स्पष्ट किया कि हम केवल राजनीति ही नहीं करते, बल्कि सभी वर्गों की समस्याओं को भी समझने का प्रयास करते हैं। प्रदेशाध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे ने नए प्रवेशकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, आज आप जिस ताकत के साथ पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उससे हमारी पार्टी की ताकत और बढ़ेगी। अब हमें 'अजितपर्व' को आगे बढ़ाते हुए भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना है। इस अवसर पर विधायक प्रतापराव चिखलीकर-पाटिल, विधायक शिवाजीराव गर्जे, विधायक इंद्रीस नायकवाडी, मुख्य प्रवक्ता आनंद परांजपे, सहकोषाध्यक्ष संजय बोरगे, प्रदेश महासचिव लतीफ तांबोळी आदि उपस्थित थे।

वाल्मिक कराड के कहने पर महादेव गिते पर हमला: जितेंद्र आव्हाडने शेयर किया 'वह' वीडियो

जमीर काज़ी मुंबई: बीड जिले के परली तालुका के मरळवाडी गांव के सरपंच बापू आंधळे की पिछले साल २९ जून को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के नेता जितेंद्र आव्हाड ने दावा किया है कि यह कृत्य वर्तमान में न्यायिक हिरासत में चल रहे वाल्मिक कराड के कहने पर किया गया था। इस संबंध में, आव्हाड ने हमले में घायल महादेव गिते का वीडियो ट्वीट करते हुए साझा किया है।

परली शहर के बैंक कॉलोनी क्षेत्र में यह घटना घटी थी, जिसमें बापू आंधळे की मौके पर ही मौत हो गई थी। महादेव गिते पर वाल्मिक कराड के कहने पर हमला किए जाने का आरोप लगाया गया है। घायल व्यक्ति का अंबाजोगाई मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान का वीडियो आव्हाड ने शेयर किया है। इस वीडियो से मामला और भी गर्मा गया है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वाल्मिक कराड की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

महादेव गिते ने, जिस पर वाल्मिक कराड के कहने पर हमला हुआ था, इलाज के दौरान पिछले साल २ जुलाई को अंबाजोगाई मेडिकल कॉलेज में एक वीडियो बनाया था। मामला क्या है? अजित पवार गुट के सरपंच बापू आंधळे की २९ जून २०२४ को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुरानी दुश्मनी के चलते उनकी हत्या की गई थी। परली शहर के बैंक कॉलोनी इलाके में उन पर गोलीबारी हुई थी। इस मामले में बबन गिते, मुकुंद गिते, महादेव गिते, राजाभाऊ निहरकर और राजेश वाघमोडे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। वहीं, दर्ज की गई एक अन्य शिकायत में मंत्री धनंजय मुंडे के करीबी वाल्मिक कराड सहित सात लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, जांच में वाल्मिक कराड की संलिप्तता नहीं पाई गई थी और उनका नाम इस मामले से हटा दिया गया था। लेकिन अब, जितेंद्र आव्हाड द्वारा किए गए ट्वीट के बाद यह मामला फिर से चर्चा में आ गया है।

राज्य के सभी जिलाधिकारी कार्यालयों में मुख्यमंत्री सहायता निधि कक्ष

विशेष संवाददाता मुंबई: राज्य के जरूरतमंद रोगियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य के सभी जिलाधिकारी कार्यालयों में मुख्यमंत्री सहायता कक्ष शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पहले कार्यकाल में जरूरतमंदों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय में मुख्यमंत्री सहायता निधि कक्ष की शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने निर्देश दिया था कि यह सेवा नागरिकों को उनके ही जिले में आसानी से उपलब्ध होनी

चाहिए। इसी के तहत राज्य के सभी जिलाधिकारी कार्यालयों में मुख्यमंत्री सहायता कक्ष शुरू करने का शासनादेश जारी किया गया है। इस कक्ष में प्रस्तुत आवेदनों का फॉलो-अप करने के लिए रोगी और उनके परिजन मंत्रालय आते हैं। इस निर्णय से नागरिकों को मुख्यमंत्री सहायता निधि से संबंधित मामलों की जानकारी उनके जिले में ही मिल जाएगी। मुख्यमंत्री सहायता निधि कक्ष के प्रमुख रमेश्वर नाइक ने बताया कि फडणवीस के मार्गदर्शन में इस कक्ष का संचालन अधिक सरल और पेपरलेस किया जा रहा है।

महंगे चिकित्सा उपचार के लिए जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस की जा रही है, जिससे अब इस प्रक्रिया के लिए मंत्रालय आने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए जल्द ही एक स्वतंत्र ऑनलाइन प्रणाली विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता निधि के माध्यम से गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए जरूरतमंद नागरिकों को आवश्यक आर्थिक मदद दी जाती है। इस सेवा का लाभ अधिक से अधिक लोगों को सरलता से मिल

सके, इस उद्देश्य से जिलाधिकारी कार्यालयों में मुख्यमंत्री सहायता निधि कक्ष शुरू किया जाएगा। संबंधित जिलों के मुख्यमंत्री सहायता कक्ष में प्राप्त आवेदनों की वर्तमान स्थिति नागरिकों को प्रदान करना, समस्याओं का समाधान करना, आए हुए मरीजों के परिजनों को आवेदन भरने में मदद करना, मुख्यमंत्री सहायता निधि से आर्थिक सहायता प्राप्त मरीजों से अस्पताल जाकर मिलना, इस कक्ष के बारे में जागरूकता और प्रचार करना, जिले में आपदा प्रभावित स्थानों का दौरा करना और आर्थिक सहायता के लिए बीमारियों की समीक्षा कर नई

सहायता राशि तय करना, इन सभी कार्यों के लिए राज्य के विशेषज्ञ डॉक्टरों की समिति का गठन किया गया है। इससे आर्थिक सहायता प्राप्त करने योग्य बीमारियों की संख्या में वृद्धि होगी और बढ़ते उपचार खर्चों को ध्यान में रखते हुए सहायता राशि की भी समीक्षा की जाएगी। नाइक ने कहा कि मुख्यमंत्री सहायता निधि कक्ष के माध्यम से कई गंभीर बीमारियों के उपचार पर आने वाले खर्च के लिए मरीजों को आर्थिक मदद दी जाती है। साथ ही, आपदाओं के समय भी आर्थिक

सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रक्रिया को और सुविधाजनक बनाने के लिए धर्मार्थ अस्पताल सहायता कक्ष की ऑनलाइन प्रणाली (चैरिटी पोर्टल) और मुख्यमंत्री सहायता निधि कक्ष की ऑनलाइन प्रणाली (सीएमआरएफ पोर्टल) को एकीकृत किया जाएगा। वर्तमान कार्य प्रणाली के अनुसार, मरीज को दिया जाने वाला एओ नंबर और एम नंबर को एकीकृत किया जाएगा। इस सुविधा से निधि के आवेदन की प्रक्रिया और तेज और सरल हो जाएगी।

